प्रेषक.

डी०एस० गर्ब्याल, संविव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादुन।

शहरी विकास अनुमाग-2

देहरादून : दिनांक :/ ७ अक्टूबर, 2016

विषय:

प्रधानमंत्री आवास योजना के Affordable Housing Project (AHP) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत 02 डी०पी०आ२० की केन्द्रांश की धनशशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय.

जपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के पत्र स0—482 / सूडा / 2016—17. दिनाक 19.09.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक PAO/Scett/UD/ADMN/Grants-in-Aid/Advices/2016-17/1342-43, दिनांक 01.09.2016 के द्वारा अवमुक्त किये गये केन्द्रांश ₹ 1.39.82.270 / — एवं पत्र संख्या PAO/Scett/UD/ADMN/Grants-in-Aid/Advices/2016-17/1344-45, दिनांक 01.09.2016 के द्वारा अवमुक्त किये गये केन्द्रांश ₹ 1.38,57,730 / — अर्थात् कुल केन्द्रांश ₹ 278.40 लाख अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

- 2— उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय के उक्त दोनों पत्रों दि0—01.09.2016 एवं भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के पत्र संख्या N-11036/31/2015-Pt/HFA-1(FTS-16359) दिनांक 29.09.2016 द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश ₹ 1,39.82,270/— एवं पत्र संख्या—11036/31/2015-Pt/HFA-1(FTS-16359) दिनांक 29.09.2016 द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश ₹ 1,38,57,730/— अर्थात् कुल स्वीकृत केन्द्रांश की धनसंशि ₹ 278.40 लाख (₹ दो करोड़ अठ्हत्तर लाख चालीस हजार मात्र) निम्न प्रतिबन्धों/शतौं के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं.—
  - (i) उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
  - (ii) उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की गाईड लाईस/दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।
  - (iii)धनराशि का व्ययं किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।



- (iv) जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, <u>उसी पर व्यय</u> किया जाएगा। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (v) योजनान्तर्गत बनाये जाने वाले कुल आवासों में अनुसूचित जाति के न्यूनतम 19 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के 04 प्रतिशत व्यक्तियों को अवश्य ही लामान्वित किया जायेगा एवं विद्तीय एवं मौतिक प्रगति विवरण में सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लामार्थियों का विवरण पृथक-पृथक अंकित करते हुए नोडल एजेन्सी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (vi) योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईड लाईन्स, सी0एस0एम0सी0 बैठकों में लिये गये निर्णयों एवं केन्द्रांश अवमुक्त सम्बन्धी भारत सरकार के पत्र संख्या N-11036/08/2015-HFA-1/FTS-13677, दिनांक 26.04.2016 में उल्लिखित प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित जायेगा।
- (vii) वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-490/XXVII(1)/2016, दि0नांक 31.03.2016 एवं शासनादेश संख्या 847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26.07.2016 में दिए गए दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) उक्त धनसिश का दि0—31.03.2017 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 3— जक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016—17 के आय—व्ययक के अनुदान सं0
  13 के लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित
  विकास—आयोजनागत—800—अन्य व्यय—01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
  —13—हार्फसिंग फॉर ऑल(90:10)—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे

  ₹ 138.58 लाख तथा अनुदान सं0—30 के लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम
  श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत—800—अन्य व्यय—01—आयोजनागत/केन्द्र
  पुरोनिधानित योजनाएं—09—हार्फसिंग फॉर ऑल(90:10)—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज
  सहायता के नामे ₹ 139.82 लाख डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26.07.2016 में दिये गये निर्देशों के कम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न अलॉटमेन्ट आईडी 18../6/0/3 0/4 ह

भवदीय.

(डी०एस० गर्ब्याल) सचिव।

कमशः.../3

## संख्या- 1 788 IV(2)-श0वि0-2016-92(सा0)/14, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड शासन।
- 3. निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी, उत्ताराखण्ड।
- 4. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
- जिलाधिकारी, देहरादुन ।
- बित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून ।
- 7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- वित्तं अनुभाग–2, उत्ताराखण्ड शासन।
- निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
- 10. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, देहरादून।
- भा. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 14. गार्ड फाईल ।

0/

आज्ञा से, (गजेन्द्र सिंह कफलिया) अनु सचिव।

